यूपी में बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ रहे जातिवादी सामंतों को योगी सरकार का खुला संरक्षण

लखनऊ (म. मो.) रिहाई मंच ने बलिया और बदायूं में बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किये जाने और मुज़फ्फरनगर में दलित नौजवान को पीट-पीटकर मार दिए जाने पर रोष प्रगट करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में दलित उत्पीड़न चरम पर है। बाबा साहेब की मूर्ति लगातार मनुवादी ताकतें तोड़ रही हैं और दलितों को पीट-पीटकर मारा जा रहा है। मुज़फ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में दलित युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया और सामंतों को संरक्षण देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री 'दलित-मित्र' के सम्मान से सम्मानित होकर समाज का मजाक उड़ा रहे हैं।

रिहाई मंच नेता लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि योगी के सत्ता में आने के बाद बलिया दलित-उत्पीड़न का अड्डा बन गया है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामंतों को संरक्षण दे रहे हैं। रसड़ा में गाय के नाम पर दलितों को पिटवाने वाले कौशलेन्द्र गिरि मुख्यमंत्री की जाति के हैं और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ढेकवारी गाँव में बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ने वालों को पता है कि भाजपा उनके साथ है और उन पर कोई कार्यवाही नही होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को बाबा साहेब के संविधान से डर लगता है इसलिए उनकी मूर्तियों को अपने गुर्गों से तोड़वा रही है।

मंच के महासचिव राजीव यादव ने पिछले दिनों मुज़फ्फरनगर केल्हनपुर निवासी विपन कुमार से मुलाकात की जिन पर बौद्ध धर्म अपनाने के नाम पर ब्राहमण जाति के लोगों ने जानलेवा हमला करके जय श्री राम और जय माता दी के नारे लगवाए थे।

14 जनवरी की घटना के बाद आज तक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपडेट करने वाले व तमंचे से डराने धमकाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंच ने कहा कि मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर और रुड़की में समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। जनवरी में सहारनपुर के गाँव डंडी में दलितों के ऊपर हमला करने वाले सवर्ण-सामन्ती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही न करके सरकार सवर्ण अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। 2 अप्रैल के दलित बंद के बाद आज तक लगातार आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारियां और उत्पीड़न जारी है।

बलात्कारी विधायक है पुराना संघी, इसलिए योगी नहीं कर पाये उस पर हाथ डालने की हिम्मत

पेज एक का शेष

सरस्वती के विरुद्ध चल रहे बलात्कार के एक मुक़दमे को वापस लिए जाने के आदेश संबंधी पत्र शाहजहांपुर जिला प्रशासन को भेजा है।

जबकि बलात्कार पीड़िता ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सरकार के इस क़दम को सवालों में खड़ा करते हुए चिन्मयानंद के खिलाफ़ वारंट जारी करने की मांग की है। वहीं योगी सरकार के गृह विभाग ने शाहजहांपुर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद पर धारा 376 (बलात्कार) और 506 (धमकाने) के तहत दर्ज मुक़दमा वापस लिए जाने का आदेश जिला प्रशासन को जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक एसआर दारापुरी कहते हैं उन्नाव गैंगरेप ने हमारी क्रिमिनल जस्टिस व्यवस्था और मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को नंगा कर दिया है।

उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का एक ओडियो भी मीडिया में सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायक पीड़ित के परिवार को धमका रहे है और मामले को खत्म करने का दबाव

बना रहे है। कुलदीप सिंह ने आडियो में यह भी स्वीकारा है कि मारपीट क्यों की गई। बीजेपी विधायक पीड़ित परिवार से कहते दिखाई दे रहे हैं, हमारे खिलाफ पर्चा क्यों लगवाते हो?

इस कांड पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लिखते हैं, बेटी बचाओ-खुद मारे जाओ। एक युवती भाजपा विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाती है। एमएलए को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस युवती के पिता को हिरासत में ले लेती है। उसके तुरंत बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं आरोपी भाजपा विधायक अभी भी खुले घूम रहे हैं।

बलात्कार पीड़ित युवती के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) एसपी चौधरी कहते हैं, जब पीड़िता के पिता को अस्पताल लाया गया था तो उसकी आंत में गंभीर चोट लगी थी। गंभीर चोट की वजह से उसकी मौत हुई। आंत फटने की वजह से इंफेक्शन हुआ, जिससे उसकी मौत हुई।

उन्नाव गैंगरेप में बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने सरकार पर ही तंज कसते हुए लिखा है, सरकार को बेटी बचाओ का नारा बदलकर बेटी हमसे बचाओ कर देना चाहिए। बीजेपी के विधायक ही आपके नारे का मजाक बना रहे हैं। पीड़िता के पिता की जेल में हत्या कर दी गई? हिंदू होने का दावा न करें, क्योंकि आप महिलाओं को देवी की नजर से नहीं देखते हैं। ऐसे में अब इस पाखंड को बंद करें।'

पीपीपी मोड का कमाल बीके अस्पताल में बिना डॉक्टरों के होता डायलेसिस

पेज एक का शेष

उस पर मुनाफ़ा जोड़ कर वसूलता है। जबकि बीके अस्पताल में धंधा करने वाली कम्पनी को न तो डॉक्टरों पर कुछ खर्च करना और अस्पताल व इन्फ्रास्ट्रक्चर तो सरकारी है ही। ऐसे में कम्पनी की लूट कमाई किसी भी व्यापारिक अस्पताल से कम नहीं बैठती।

कम्पनी का धंधा शुरू कराने से पूर्व सरकारी योजनानुसार एक विशेषज्ञ डॉक्टर भगत को लाखों के सरकारी खर्च पर इस विधा की ट्रेनिंग हेतु 10 माह के लिये रोहतक मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। वे ट्रेंड होकर आ भी गये तो उन्हें बजाय डायलेसिस कम्पनी के साथ जोड़ने के एक डिस्पेंसरी में बैठा दिया। क्योंकि धंधा करने वाली कम्पनी नहीं चाहती कि कोई सरकारी डॉक्टर उनके सिर पर सवार होकर उनकी निगरानी करे।

पीपीपी मोड का मतलब कहने को तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। लेकिन इसका असल मतलब होता है पूंजी अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिक का और मुनाफ़ा प्राइवेट यानी प्राइवेट कम्पनी का। इसी तरह का घिनौना खेल ईएसआईसी के स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलाया गया था। लेकिन पिछले दिनों कार्पोरेशन के डीजी ने इसे शीघ्रातिशीघ्र बन्द करने के आदेश दे दिये हैं।

मोटी रिश्वत से बनते रहे शस्त्र लाइसेंस....

पेज एक का शेष

कर्मचारी जो आंखें मीच कर अपने छोटे-मोटे लालच के पीछे, अफ़सरों के कहने पर ग़लत रिपोर्ट तैयार करता है।

'मज़दूर मोर्चा' द्वारा की गयी तहकीकात में पाया गया कि सतबीर पुत्र टेकराम भाटी (गूजर) पर थाना दादरी में करीब 18 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। इसके चलते वह उस थाने का हिस्ट्री सीटर (दस नम्बरी बदमाश) है। नियमानुसार थाने की पुलिस अपने ऐसे हिस्ट्री सीटरों पर कड़ी नजर रखती है। नज़र से ओझल होने पर उसकी तलाश करती है। उसका नया ठिकाना पता लगने पर उस क्षेत्र के सम्बन्धित थाने को उसके पिछले रिकार्ड से अवगत कराया जाता है। इस हिसाब से थाना भोपानी को सतबीर के रिकार्ड से अवगत होना चाहिये था। लेकिन जब आंखें मीचनी हो तो रिकार्ड को खुर्द-बुर्द करना क्या मुश्किल है।

जब सतबीर ने अपने नये पते मकान नम्बर 120 गांव मवई से पिस्टल/ रिवाल्वर के लिये आवेदन किया तो थाना भोपानी के तत्कालीन एएसआई बह्म प्रकाश ने उसके पते की तस्दीक कर दी। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रबन्धक इन्स्पेक्टर संदीप मोर ने सिफ़ारिश करते हुए अपने रिपोर्ट में लिखा कि आवेदक की उत्तर प्रदेश व राजस्थान में ज़मीनें हैं, जहां से पैसे का लेद-देन करने के लिये उसे आना-जाना पड़ता है। इसलिये इसे लाइसेंस दे दिया जाय। इसी सिफारिश को तत्कालीन एसीपी मुख्यालय ने भी मान लिया। उसके बाद अप्रैल 2016 डीसीपी बिरेन्द्र विज ने भी उन तमाम सिफ़ारिशों पर अपनी मुहर लगा दी। इन्हीं तमाम सिफ़ारिशों की आड़ में ज्वायंट सीपी ने सतबीर को लाइसेंस नम्बर 100/16 जारी कर दिया।

अब देखना है कि सीपी ढिल्लों साहब किस स्तर तक के अधिकारी का गला नापने की हिम्मत जुटा पाते हैं।

सम्पादक के नाम

गरीब तंग है बैंक कर्मियों से

संपादक जी

आपने मजदूर मोर्चा अखबार के ताजा अंक (25-31मार्च 2018) में बैंक कर्मियों की परेशानी पर रवीश कुमार का लेख छापा। उनकी परेशानियाँ वाजिब हैं। यह सच है कि, आज के समय में, बैंक मैनेजमेंट उनका बहुत शोषण कर रही है। पर इस सच का दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करना आवश्यक है। और उसी के माध्यम से शायद बैंक कर्मियों के लिए राहत के रास्ते भी निकलेंगे।

इन्ही बैंक कर्मियों का व्यवहार गरीब लोगों के साथ निहायत ही शर्मनाक होता है। बहुत थोड़ा समय था जब मोदी जन धन अभियान के तहत गरीबों के खाते खुल रहे थे पर अब फिर वही पहले जैसी स्थिति है। गरीब आदमी के लिए खाता खुलवाना आसान नहीं है। काम करनेवाली लड़की ने बताया कि वो बार बार (अब तक 6 बार) state bank india में खाता खुलवाने के लिए चक्कर काट चुकी है। उसको state bank india में खाता खुलवाना इसलिए जरूरी है की वहीं पर उसका scholarship का पैसा आना है। एक state bank शाखा ने सीधे यह कह कर उसे भगा दिया कि उसका खाता नहीं खुल सकता। दूसरी शाखा ने कहा कि खाता खुलवाने के लिए 5000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। एक और ब्रांच ने बताया की कम से कम 3000 रुपये का बैलेंस रखना होगा। जब वो पैसा इक्कट्ठा कर कर पहुंची तो दो तीन चक्कर तो फॉर्म देने और उसकी कागजी कार्यवाही में लगा दिए और जब जा कर फॉर्म स्वीकार किया। पैसे अभी भी जमा नहीं हुए। एक बैंककर्मी ने कहा कि जब समय मिलेगा खाता खोल दिया जायेगा।

इसका जिक्र जब मैंने अपने एक अध्यापक मित्र से किया तो उन्होंने बताया कि उनके गाँव में (ग्राम सोनवल, पूर्वी चंपारण बिहार) उनका भी यही तर्जुबा है। अभी महीना भर पहले जब वो अपनी नवोदय विद्यालय में पढने वाली बेटियों का बैंक खाता खुलवाना चाहते थे तो किस्म किस्म के अवरोधों का सामना करना पड़ा। आधार कार्ड तो था पर उन छोटी बच्चियों का पैन कार्ड बनवाना पड़ा। statebank ने पहले तो कहा कि खाता खुल ही नहीं सकता। वो punjab national bank गए तो उन्होंने भी खाता खोलने से इनकार कर दिया। कई चक्कर लगाने के बाद और यह बताने के बाद कि वो DU के अध्यापक हैं statebank मेनेजर ने उन्हें एक सर्विस सेंटर पर भेजा जिसने processing फीस के नाम पर 324 रुपये की मांग की। उनके यह पूछने पर कि क्या वो पैसा उनके खाते में जमा होगा तो उन्हें बताया गया कि नहीं। मेरे मित्र ने उनको वहां भेजने वाले बैंक मेनेजर से इसकी शिकायत की तो service सेंटर वाला नाराज हो गया और खाता नहीं ही खुला।

मेरा पक्का विश्वास है कि फरीदाबाद में आम मजदूरों और अन्य लोगों का तर्जुबा भी इससे अलग नहीं होगा।

बैंक मैनेजमेंट की तानाशाही से परेशान बैंक कर्मी भाइयों और बहनों को समझना होगा की आम लोगों से उनके व्यव्हार के बारे में बैंक हुक्मरान जानते हैं। उन्हें पता है समाज में उनकी कोई साख नहीं है। कोई उनके साथ नहीं आने वाला। इसलिए जो मर्जी करो सब चलेगा। अगर इस सबसे निजात पानी है तो उन्हें अपने ग्राहक खास कर गरीब ग्राहकों से मजबूत दोस्ती बनानी होगी तभी और केवल तभी उनकी समस्याओं का दूरगामी समाधान हो सकता है। बैंक हुक्मरानों पर एक मानवीय काम के माहौल का दबाव बनाया जा सकता है। नहीं तो रवीश कुमार के सहयोग से तात्कालिक कुछ राहत बेशक मिल जाये पर यह मुहिम ज्यादा दूर नहीं जाने वाली।

सादर
रवींद्र गोयल

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
6. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक**
10. **आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद**